भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293] No. 293] दिल्ली, बुधवार, अगस्त 2, 2017/श्रावण 11, 1939

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 192

DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 2, 2017/SRAVANA 11, 1939

[N.C.T.D. No. 192

भाग—IV PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि एवं भवन विभाग

(प्रशासन शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 1 अगस्त, 2017

सं. फा. 05 (29)/16/एल एंड बी/प्रशा./4216.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना एस.ओ. 2740(अ), दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 तथा एस.ओ. 2004(अ) दिनांक 21 जुलाई, 2015 के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 13) की धारा 51 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित लोगों के भूमि अधिग्रहण, प्रतिपूर्ति एवं पुर्नवास एवं पुनःस्थापन से संबंधित विवादों के शीघ्र निपटान के उद्देश्य के प्रयोजनार्थ "भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास एवं पुनःस्थापन प्राधिकरण" जिसमें पीठासीन अधिकारी होंगे, का गठन करते हैं।

भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास एवं पुनःस्थापन प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 64 या धारा 64 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अंतर्गत भेजे गए संदर्भो पर विचार करने तथा निर्णय करने के लिए समूचित सरकार द्वारा यथा अधिसूचित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्र के भीतर उक्त अधिनियम के अंतर्गत या इसे प्रदत्त क्षेत्राधिकार, शक्तियों तथा प्राधिकारों का प्रयोग करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, ए. के. केन, उप—सचिव (प्रशासन)

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

(ADMINISTRATION BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 1st August, 2017

No. F. 05/29/16/L&B/ADMN/4216.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 51 of "the Right of Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) read with Government of India, Ministry of Home Affairs, notification numbers S.O. 2740(E) dated 21st October, 2014 and S.O. 2004(E) dated 21st July, 2015, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to constitute the "Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority" consisting of Presiding Officer, for the purpose of providing speedy disposal of disputes relating to Land Acquisition, Compensation, Rehabilitation and Resettlement of the affected persons due to the acquisition of land under the provisions of the said Act.

The Land Acquistion, Rehabilitation and Resettlement Authority shall exercise the jurisdiction, powers and authority conferred on it by or under the said Act to the area within the National Capital Territory of Delhi as notified by the appropriate Government for entertaining and deciding the references made to it under section 64 or applications made by the applicants under the second proviso to sub section (1) of section 64 of the said Act.

By Order and in the Name of Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

ASHOK KUMAR KAIN, Dy. Secy. (Admn.)